भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.482
उत्तर देने की तारीख 03 दिसम्बर, 2025

वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना

482. श्री दामोदर अग्रवालः
श्री अरुण गोविलः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में उक्त 'पीएम-वाणी' योजना के अंतर्गत वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने वाली कुल कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने हेतु इन कंपनियों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन कम्पनियों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध करा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) सरकार ने देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार में तेजी लाने के लिए 9 दिसंबर 2020 को पीएम-वाणी स्कीम को मंजूरी दी। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के उद्देश्यों के अनुरूप पीएम- वाणी फ्रेमवर्क का उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल संचार अवसंरचना बनाना है। यह फ्रेमवर्क सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को न्यूनतम विनियामक निरीक्षण के साथ सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) के एग्रीगेशन के तहत वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की अनुमति देता है, इस प्रकार स्थानीय उद्यमियों को डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिनांक 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार, पीएम वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट की राज्य-वार कुल संख्या **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख) पीएम वाणी स्कीम के तहत, ग्राहक को वाई-फाई सेवाएं सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जो पीडीओए (सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर) के एजेंट होते हैं। दिनांक 26.11.2025 तक, वर्तमान में ऑन-बोर्ड पीडीओ (वाई-फाई हॉटस्पॉट) की कुल संख्या 3,91,599 है।

(ग) दूरसंचार विभाग ने पीएम वाणी के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट के प्रसार से संबंधित प्रमुख मामलों के समाधान के लिए दिनांक 16.09.2024 को मौजूदा पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) फ्रेमवर्क में निम्नलिखित प्रमुख सुधारों की शुरुआत की है:

- पीडीओ (सार्वजनिक डेटा कार्यालयों) को एक नियमित एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से पीएम वाणी प्रदान करने अनुमति दी गई थी जो उनकी लागत को कम करेगा।
- पीडीओ को व्यापक वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए एक ही बैकहॉल में अपने मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को एग्रीगेट करने की अनुमति दी गई थी।
- मौजूदा घर या व्यवसाय वाई-फाई एक्सेस पॉइंट को व्यापक पीएम- वाणी नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति दी गई, जिससे उनके मौजूदा एक्सेस पॉइंट का उपयोग राजस्व के एक स्रोत के रूप में किया गया।
- पीडीओए के बीच रोमिंग की अनुमति दी गई थी ताकि एंड यूजर विभिन्न पीडीओए के पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट के बीच आसानी से स्विच कर सकें।
- पीडीओ को मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर मोबाइल डेटा ऑफलोड प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।
- पीडीओए और ऐप प्रदाताओं को प्रयोक्ता की सहमति के बाद, संभावित पीएम-वाणी वाई-फाई प्रयोक्ताओं को कंटेंट, प्रचार और ब्रांडिंग संदेश भेजने की अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा, ट्राई ने दिनांक 16.06.2025 को सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए टैरिफ से संबंधित एक दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया। इस आदेश में उल्लिखित है कि 200 एमबीपीएस तक की सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड योजनाओं को सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड मूल्य के दोगुने से अनधिक टैरिफ पर प्रदान किया जाना चाहिए।

(घ) और (ङ) पीएम वाणी स्कीम के तहत, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पीएम वाणी हितधारकों (पीडीओ, पीडीओए और ऐप प्रदाताओं) द्वारा खरीदे जाने हैं। हितधारकों द्वारा विकसित सोल्यूशन पीएम वाणी के अनुरूप होना चाहिए जो कि पीएम वाणी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीडीओटी द्वारा प्रमाणित है।

*****

अनुबंध -I

क्र.सं.	राज्य	वाई-फाई हॉटस्पॉट की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	275
2	आंध्र प्रदेश	6074
3	अरुणाचल प्रदेश	1017
4	असम	1063
5	बिहार	4086
6	चंडीगढ़	253
7	छत्तीसगढ़	2839
8	दिल्ली	198275
9	गोवा	430
10	गुजरात	11857
11	हिमाचल प्रदेश	936
12	हरियाणा	18131
13	झारखंड	1042
14	जम्मू और कश्मीर	2299
15	कर्नाटक	21834
16	केरल	4987
17	लद्दाख	601
18	लक्षद्वीप	1
19	महाराष्ट्र	33084
20	मेघालय	256
21	मणिपुर	21
22	मध्य प्रदेश	7592
23	मिजोरम	3
24	नागालैंड	78
25	ओडिशा	3040
26	पंजाब	3713
27	पुडुचेरी	89
28	राजस्थान	2891
29	सिक्किम	13
30	तेलंगाना	4284
31	तमिलनाडु	7501
32	त्रिपुरा	310
33	उत्तराखंड	980
34	उत्तर प्रदेश	47549
35	पश्चिम बंगाल	4195
	कुल	**391599**

*****